HARI BHOOMI, Delhi, 20.12.2024
Page No. 9, Size:(3.28)cms X (6.05)cms.

पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को अहम पद देने की अटकलें

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को मोदी सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार

आयोग का अध्यक्ष बना सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने आयोग के अगले अध्यक्ष का चयन करने के लिए बैठक की। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी थे।

ORISSA POST, Bhubaneswar, 20.12.2024
Page No. 5, Size:(18.45)cms X (17.49)cms.

NHRC seeks ATR on rape of minor girl in Kandhamal

PNN & AGENCIES

Kendrapara, Dec 19: The National Human Rights Commission (NHRC) has sought an Action Taken Report (ATR) from the District Magistrate (DM) and the Superintendent of Police (SP), of Kandhamal, on the rape of a minor girl, September 1.

The NHRC Wednesday directed the DM and the SP of Kandhamal to submit the health status report of the victim, the status of the police investigation, and compensation, if any, paid to the aggrieved family.

The apex rights panel issued directions while acting on the complaint filed by rights activist Sagar Jena.

The petitioner alleged before the commission that a minor girl was subjected to rape September 1 in Kandhamal district when she had gone to the market to purchase some material for her dress.

The accused, who is reportedly a distant relative of the victim, had dragged the victim to nearby bushes where she was subjected to rape.

The accused also threatened to kill the victim if she reported the matter to anyone. The complainant has requested the commission to intervene in the matter.

Acting on the complaint, the NHRC issued direction to the DM and the SP, Kandhamal calling for a report on the matter within four weeks including the health status of the victim, the status of police investigation and compensation if any paid to the aggrieved family.

The top rights body said it would be constrained to invoke coercive process u/s 13 of the Protection of Human Rights Act, 1993 calling for a personal appearance of the authority concerned for submission of the report, in case the report is not received within the stipulated time.

GREATER KASHMIR, Srinagar, 20.12.2024
Page No. 10, Size:(24.90)cms X (12.57)cms.

NHRC discusses welfare of elderly with global experts

IANS
New Delhi, Dec 19

Suggestions on healthcare and nutritional needs of the elderly and their economic security, social inclusion, and quality of life from experts from the WHO, among others, dominated the agenda at a seminar organised by the National Human Rights Commission (NHRC) on Thursday.

Addressing the inaugural session, NHRC, Secretary General, Bharat Lal spoke about the evolving role of old age homes and the necessity for change and improvement in their functioning, a statement said.

Chairing the first thematic session on the health and nutrition needs of the elderly, Dr V. K. Paul, Member (Health), NITI Aayog, while sharing the concerns on the present and future challenges related to the well-being of the ageing population, commended the NHRC, India for its various initiatives in this regard.

Amit Yadav, Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment, chaired the second thematic session on economic security, social inclusion, and quality of life.

Several domain experts and eminent people, representatives of NGOs, academia, researchers, startups and medical fraternity attended the meet. After the speakers in each session, an open house was held to discuss the questions from the participants from various sectors including the WHO, United Nations Population Fund (UNFPA) and Tata Trusts.

The seminar 'Ageing in India: Actionable Solutions - Drawing insights from Global, Regional, and National Best Practices' was organised by the NHRC, in partnership with Sankala Foundation, along with the active participation of NITI Aayog and Ministry of Social Justice and Empowerment.

Earlier, NHRC, Secretary General, Bharat Lal emphasised that the Commission is working closely with civil society organisations, Special Rapporteurs and Monitors and human rights defenders to assess and advocate for elderly rights.

He said that it is time to work on an action-oriented model including the best practices for replication for the overall welfare of the elderly population in the country. He urged for synergy among all organisations and said that an effort was on to develop a platform to provide elderly individuals with opportunities to engage and contribute to society, meaningfully.

DAINIK TRIBUNE, Online, 20.12.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

अंबेडकर के प्रति गृहमंत्री की टिप्पणी पर विभिन्न संगठनों ने जताया रोष

https://www.dainiktribuneonline.com/news/gurugram/various-organizations-expressed-anger-over-the-home-ministers-comment-on-ambedkar/

Published At: DECEMBER 19, 2024 10:14 AM (IST)

नारनौल, 18 दिसंबर (हप्र)

डा. भीमराव अंबेडकर के प्रति गृहमंत्री अमित शाह की कथित टिप्पणी के मामले में विभिन्न संगठनों ने सर्व अनुसूचित जाति संघर्ष समिति के प्रधान चंदन सिंह जालवान की अध्यक्षता में संघर्ष समिति कार्यालय में बैठक कर रोष प्रकट किया और सामूहिक हस्ताक्षरयुक्त पत्र राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** को लिखकर ऐसी अवांछनीय टिप्पणियों पर रोक लगाने की मांग की।

बैठक का संचालन करते हुए संघर्ष समिति के महासचिव एवं कबीर सामाजिक उत्थान संस्था दिल्ली के प्रमुख सलाहकार बिरदी चंद गोठवाल ने बताया कि भारत वर्ष के संसदीय इतिहास में पहली बार देश के गृहमंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब डा. भीमराव अंबेडकर के नाम पर की गई अभद्र एवं अवांछनीय टिप्पणी – अब यह फैशन हो गया...अंबेडकर.. अंबेडकर.. अंबेडकर.. अंबेडकर.. अंबेडकर.. अंबेडकर..अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता, गृहमंत्री की सोच को

दर्शाता है।

अखिल भारतीय आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष लालाराम नाहर, गुरु रविदास महासभा के प्रधान बलबीर सिंह बबेरवाल, पूर्व डीजीएम व धानक समाज के महेंद्र खन्ना, कबीर सामाजिक उत्थान संस्था दिल्ली के प्यारेलाल चवन, भारतीय सामाजिक परिवर्तन संघ के सुमेर सिंह गोठवाल, संघर्ष समिति के सचिव हजारीलाल खटावला, पूर्व मैनेजर जयपाल सिंह व रामचंद्र गोठवाल आदि ने गृहमंत्री द्वारा की गई इस अभद्र टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि बाबा साहेब डा. भीमराव अंबेडकर उच्च कोटि के विद्वान, विधिवेत्ता, समाजशास्त्री, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और मानवीय एकता, समानता व समरसता के हितैषी थे। उनके द्वारा लिखित संविधान संसार भर में अद्वितीय है।

सारी दुनिया बाबा साहेब द्वारा रचित संविधान को श्रद्धापूर्वक नमन करती है और उनकी असामान्य प्रतिभा का लोहा मानती है। आज हम यदि तुलनात्मक दृष्टि से और निष्पक्ष दृष्टिकोण से परखते हैं तो बाबा साहेब द्वारा सृजित राष्ट्र ग्रंथ (संविधान) समय की कसौटी पर खरा उतरता है।

सीआईएसएफ ने 29वीं अंतर सीएपीएफ वाद-विवाद प्रतियोगिता में जीती ट्रॉफी

https://www.5dariyanews.com/hindi/news/298954-Central-Industrial-Security-Force-triumphs-at-29th-Inter-CAPF-Debate-Competition

Web Admin 5 Dariya News नई दिल्ली , 18 Dec 2024

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने एक बार फिर **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी)** के तत्वावधान में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा अटल अक्षय ऊर्जा भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली में आयोजित 29वीं अंतर सीएपीएफ वाद-विवाद प्रतियोगिता में ओवरऑल बेस्ट टीम रोलिंग ट्रॉफी जीती है। सीआईएसएफ यूनिट पंजाब एवं हरियाणा के सीनियर कमांडेंट श्री वाईपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब यह जीत सीआईएसएफ द्वारा इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी की 10वीं सफल जीत है और यह बल के निरंतर प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमता को भी प्रदर्शित करती है।

प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली यह प्रतियोगिता कर्मियों के लिए मानवाधिकार मुद्दों के बारे में अपने ज्ञान और समझ को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती है। प्रतियोगिता में एसआई/एक्सई राहुल कुमार और असिस्टेंट कमांडेंट कान्हा जोशी ने हिंदी भाषा वर्ग में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि अंग्रेजी भाषा वर्ग में असिस्टेंट कमांडेंट अक्षय बडोला और असिस्टेंट कमांडेंट भास्कर चौधरी ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया।

उन्होंने बताया कि सभी आठ सीएपीएफ अर्थात सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी, आरपीएफ और असम राइफल्स ने प्रतियोगिता में भाग लिया।

एनएचआरसी, भारत और संकला फाउंडेशन ने नीति आयोग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से "भारत में वृद्धावस्था: कार्यान्वयन योग्य समाधान" विषय पर एकदिवसीय सेमिनार का आयोजन किया

https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2086136

एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने देश में बुजुर्ग आबादी के समग्र कल्याण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं सहित कार्रवाई-उन्मुख मॉडल पर जोर दिया

बुजुर्ग आबादी पर एक अलग डेटाबेस विकसित करने और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक व्यापक और एकीकृत परिवार चिकित्सा कार्यक्षेत्र की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया

कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुझावों में बुजुर्गों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य और पोषण पैकेज विकसित करना, बुजुर्गों की देखभाल को सस्ती और टिकाऊ बनाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी की संभावना तलाशना, बुजुर्गों के लिए अधिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज को प्रोत्साहित करना शामिल है

Posted On: 19 DEC 2024 3:38PM by PIB Delhi

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने संकला फाउंडेशन के साथ मिलकर नई दिल्ली में नीति आयोग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की सक्रिय भागीदारी के साथ "भारत में वृद्धावस्था: कार्रवाई योग्य समाधान - वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से अंतर्दृष्टि प्राप्त करना" विषय पर एकदिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी का समापन बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल और पोषण संबंधी जरूरतों और उनकी आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक समावेशिता और जीवन की गुणवत्ता के बारे में कई महत्वपूर्ण सुझावों के साथ हुआ।

उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने वृद्धाश्रमों की उभरती भूमिका और उनके कामकाज में बदलाव और सुधार की आवश्यकता के बारे में बात की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आयोग नागरिक समाज संगठनों, विशेष प्रतिवेदकों और निगरानीकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि बुजुर्गों के अधिकारों की वकालत की जा सके। उन्होंने कहा कि देश में बुजुर्ग आबादी के समग्र कल्याण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं सहित एक क्रिया-उन्मुख मॉडल पर काम करने का समय आ गया है। उन्होंने सभी संगठनों के बीच तालमेल का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि बुजुर्ग व्यक्तियों को समाज में सार्थक रूप से जुड़ने और योगदान करने के अवसर प्रदान करने के लिए एक मंच विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री मोनाली पी. धकाटे ने भारत में वृद्धों और वृद्ध होती आबादी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007, अटल वयो अभ्युदय योजना के प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र कुमार निम ने भारत में बुजुर्ग नागरिकों के समक्ष उपस्थित कठिन समस्याओं पर प्रकाश डाला तथा बुजुर्गों की देखभाल के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की जा रही पहलों के बारे में बताया।

संकला फाउंडेशन की विजिटिंग फेलो डॉ. आभा जायसवाल ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि भारत बढ़ती उम्रदराज आबादी की चिंताओं का सामना कर रहा है। इसलिए उनके लिए एक व्यापक देखभाल तंत्र की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन जरूरतों पर ध्यान देने से आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण दोनों के लिए महत्वपूर्ण अवसर मिल सकते हैं।

बुजुर्गों की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर पहले विषयगत सत्र की अध्यक्षता करते हुए नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी.के. पॉल ने वृद्ध आबादी के कल्याण से संबंधित वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों पर चिंता व्यक्त करते हुए इस संबंध में एनएचआरसी, भारत की विभिन्न पहलों की सराहना की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव श्री अमित यादव ने आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक समावेशिता और जीवन की गुणवत्ता पर दूसरे विषयगत सत्र की अध्यक्षता की। इस बैठक में कई डोमेन विशेषज्ञ और प्रख्यात हस्ती, गैर सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, स्टार्टअप और चिकित्सा बिरादरी के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रत्येक सत्र में वक्ताओं के भाषण के बाद, डब्ल्यूएचओ, यूएनएफपीए और टाटा ट्रस्ट जैसे संगठनों सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभागियों के सवालों पर चर्चा करने के लिए एक खुले सत्र का आयोजन किया गया।

संगोष्ठी में उभरे कुछ प्रमुख सुझाव इस प्रकार थे-

i.) बुजुर्गों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य और पोषण पैकेज विकसित करना;

ii.) बुजुर्ग महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष सेवाएं सृजित करना;

iii.) घर और परिवार-आधारित देखभाल पहल को बढ़ावा देना;

iv.) बुजुर्गों की देखभाल के लिए मौजूदा सरकारी योजनाओं और मॉडलों को मजबूत करना;

v.) बुजुर्गों की देखभाल को किफायती और टिकाऊ बनाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी की संभावनाएं तलाशना;

vi.) बुजुर्गों के लिए अधिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज को प्रोत्साहित करना;

vii.) बुजुर्गों की देखभाल के संबंध में भारत के दृष्टिकोण को सुदृढ़ बनाने के लिए दुनिया की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना;

viii.) स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक व्यापक और एकीकृत पारिवारिक चिकित्सा क्षेत्र विकसित करना;

ix.) समाज में बुजुर्ग आबादी की गरिमा, अच्छे स्वास्थ्य और स्वतंत्रता के साथ भागीदारी सुनिश्चित करना;

x.) लक्षित हस्तक्षेप के लिए बुजुर्ग आबादी पर एक अलग डाटाबेस रखना;

xi.) बुजुर्गों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए नगरपालिकाओं सहित स्थानीय निकायों के साथ-साथ सार्वजनिक और निजी दोनों हितधारकों की भागीदारी की गुंजाइश तलाशना;

xii.) यह सुनिश्चित करना कि बुजुर्गों की आवाज को उनकी भलाई के लिए उचित ध्यान के साथ सुना जाए।

प्रतिभागियों में शामिल थे: डॉ. मनश्वी कुमार, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; श्री सीके मिश्रा, पूर्व सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; डॉ. के. मदन गोपाल, सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र; डॉ. संजय वाधवा, प्रोफेसर और प्रमुख, भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास विभाग, एम्स, नई दिल्ली; प्रो. राम बारू, प्रोफेसर, जेएनयू; प्रोफेसर (डॉ.) मनोहर अगनानी, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, भोपाल; डॉ. तनुजा नेसारी, पूर्व निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान; श्री मनोहर लाल बहारानी, अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक मंच; श्री पुनीत कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय विभाग, केरल; सुश्री उमा देवी, संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय विभाग, तमिलनाडु; सुश्री कजरी विश्वास, वरिष्ठ निदेशक, विदेश मंत्रालय; सुश्री अनुपमा दत्ता, हेल्पेज इंडिया; सुश्री पवित्रा रेड्डी, सीओओ, व्याह विकास; श्री पीयूष कुमार, संस्थापक, ख्याल ऐप; श्री आशीष गुप्ता, सह-संस्थापक, समर्थ एल्डरली केयर, डॉ. जीपी भगत, संस्थापक, SHEOWS, श्री के. श्रीनाथ रेड्डी, मानद प्रतिष्ठित प्रोफेसर, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, सुश्री अमृता कंसल, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, हेल्दी एजिंग वर्टिकल, डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र और डॉ. मंजरी चतुर्वेदी, सीईओ, हेल्दी एजिंग इंडिया आदि।

यह बैठक 18 अक्टूबर 2024 को आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की फॉलोअप थी, जिसमें बुजुर्गों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा की गई थी। यह चर्चा उन चुनौतियों का समाधान खोजने पर केंद्रित थी। एनएचआरसी, भारत विभिन्न हितधारकों के साथ काम करता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की विभिन्न सरकारें और उनके अर्ध-सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, मानवाधिकार रक्षक और शोधकर्ता शामिल हैं।

मोदी सरकार पूर्व CJI चंद्रचूड़ को दे सकती है यह बड़ा अहम पद, अंतिम मुहर लगना बाकी

https://www.jansatta.com/national/modi-government-can-give-this-important-post-nhrc-chief-to-supreme-court-former-cji-chandrachud-final-approval-is-yet-to-be-given/3738854/

Modi Government: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)के अगले अध्यक्ष का चयन करने के लिए बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे।

Written by न्यूज डेस्कEdited by Vivek Awasthiनई दिल्लीUpdated:December 19, 2024 16:01 IST

Modi Government: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को मोदी सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का अध्यक्ष बना सकती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अगले अध्यक्ष का चयन करने के लिए बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि समिति में शामिल विपक्ष के सदस्यों ने अध्यक्ष और एक सदस्य के लिए सरकार की पसंद पर असहमति जताई है।सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा के 1 जून को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद से एनएचआरसी अध्यक्ष का पद रिक्त है। तब से एनएचआरसी सदस्य विजया भारती सयानी को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भारत के पूर्व सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज को चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा एनएचआरसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सूत्रों ने यह भी बताया कि विपक्षी सदस्य जल्द ही अपना असहमति पत्र सौंप सकते हैं, लेकिन उन्होंने बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में बोलने से इनकार कर दिया। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में अधिसूचना जल्द ही जारी कर दी जाएगी।

ऐसे में एनएचआरसी के प्रमुख के लिए जिन नामों पर अटकलें लगाई जा रही हैं, उनमें हाल ही में सेवानिवृत्त हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का नाम भी शामिल है। चंद्रचूड़ 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू और केजी बालाकृष्णन भी एनएचआरसी के प्रमुख रह चुके हैं।

एनएचआरसी के पूर्व अध्यक्षों की सूची

भारत के मुख्य न्यायाधीशों (सीजेआई), जिन्होंने एनएचआरसी के अध्यक्ष का पद संभाला, उनमें न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा 12 अक्टूबर 1993 से 24 नवंबर 1996 तक; न्यायमूर्ति एमएन वेंकटचलैया 26 नवंबर 1996 से 24 अक्टूबर 1999 तक; न्यायमूर्ति जेएस वर्मा 4 नवंबर 1999 से 17 जनवरी 2003 तक; न्यायमूर्ति एएस आनंद 17 फरवरी 2003 से 31 अक्टूबर 2006 तक; न्यायमूर्ति एस राजेंद्र बाबू 2 अप्रैल 2007 से 31 मई 2009 तक; न्यायमूर्ति केजी बालाकृष्णन 7 जून 2010 से 11 मई 2015 तक; न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू 29 फरवरी, 2016 से 2 दिसंबर, 2020 तक और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा 1 जून, 2021 से 1 जून, 2024 तक।

सीजेआई चंद्रचूड़ को यह अहम जिम्मेदारी सौंपेगी मोदी सरकार, खाका तैयार...अंतिम मुहर का इंतजार!

https://navbharatlive.com/india/modi-government-will-hand-over-responsibility-of-nhrc-chairman-to-cji-chandrachud-1075055.html

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को मोदी सरकार एक अहम जिम्मेदारी देने वाली है। सूत्रों के मुताबिक बीते कल एक बैठक में इसे लेकर चर्चा की गई है। कहा जा रहा है कि विपक्ष ने इस पर असहमति भी जताई है।

- By अभिषेक सिंह

Updated On: Dec 19, 2024 | 06:30 PM

नई दिल्ली: मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने बीते कल यानी बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अगले अध्यक्ष का चयन करने के लिए बैठक भी की थी। जिसके बाद ऐसी अटकलें लगाईं जा रही हैं।

बुधवार को हुई इस अहम बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि समिति में शामिल विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष और एक सदस्य के लिए सरकार की पसंद से असहमति जताई है।

1 जून से खाली है पद

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा के 1 जून को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद से एनएचआरसी के अध्यक्ष का पद खाली है। तब से एनएचआरसी की सदस्य विजया भारती सयानी को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भारत के किसी पूर्व सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज को एनएचआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है।

सूत्रों ने यह भी बताया कि विपक्षी सदस्य जल्द ही अपना असहमति पत्र सौंप सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने बैठक में लिए गए फैसले के बारे में बोलने से इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख के लिए जिन नामों पर अटकलें लगाई जा रही हैं, उनमें हाल ही में सेवानिवृत्त हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का नाम भी शामिल है। बता दें कि चंद्रचूड़ 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू और केजी बालाकृष्णन भी एनएचआरसी के प्रमुख रह चुके हैं।

Bengaluru real estate: Can homebuyers approach Human Rights Commission if the builder delays in handing over the flat?

https://www.msn.com/en-in/news/India/bengaluru-real-estate-can-homebuyers-approach-human-rights-commission-if-the-builder-delays-in-handing-over-the-flat/ar-AA1w8njS?ocid=finance-verthp-feeds

Story by Souptik Datta • 22h • 3 min read

Distressed over the delay in getting possession of his apartment and the compensation ordered by RERA, a homebuyer in Bengaluru has now approached the National Human Rights Commission.

The NHRC, in turn, wrote to the Karnataka State Human Rights Commission (KHRC), which has now written to the Karnataka RERA secretary and the deputy commissioner of the revenue department to take action and submit a report on the action taken to help the buyer, documents accessed by HT.com show.

“The delay is not just a breach of trust but also a violation of our fundamental right to a dignified life,” the buyer said in his complaint.

Sudhakar Lakshmanaraja has been waiting for five years for his apartment in north Bengaluru to be delivered. The project was to be handed over by 2019.

"Despite multiple KRERA orders addressed to the deputy commissioner (revenue department) to recover the penalty from the builder, the builder has not paid us anything. Nothing has been resolved. As a last resort, I have approached the National Human Rights Commission and am waiting for justice," Lakshmanaraja was quoted as saying.

Submit report by January 9: KHRC

KHRC has written to the deputy commissioner of the revenue department that despite Lakshmanaraja's complaint to KRERA to recover the funds for the delayed apartment, the district collector's office is not following the orders of Karnataka RERA for the last two years.

“Take appropriate action and submit a report by January 9, 2024,” the notice sent on December 4 said.

This is what legal experts have to say

Legal experts say when a project is delayed in the state, the homebuyers can file a complaint at KRERA to recover their money. On its order, the state's revenue

department will recover the amount, in the form of land arrears, from the respective developers.

In some cases, homebuyers have already invested over 80% of their savings to buy homes. "With multiple KRERA orders left to be fully executed and slow recovery at the revenue department, the homebuyers have started approaching the Commission as a last resort," Advocate Reynold D'souza said.

"After KRERA issues the recovery order, the deputy commissioner's office (revenue dept) will notify the builder and recover the money. It is collected as revenue from land arrears. However, a slow recovery has left the homebuyers with no choice," Vittal BR, an advocate at the High Court of Karnataka, said.

According to a KRERA document dated August 2024, the Karnataka developers owe homebuyers more than ₹486 crore in refunds for delayed apartment delivery.

Can buyers file a complaint with the Human Rights Commission if their homes are delayed?

Legal experts said that after receiving a complaint, the Commission sends a notice to the respective government bodies to submit compliance reports.

"In this case, the Commission will send notice to the Karnataka RERA and the deputy commissioner (revenue department) to file their compliance reports within a certain period of time. This can be done to protect the homebuyers' right to life as they have invested significant funds and savings to purchase their dream homes," D'souza added.

Legal experts say that while homebuyers can approach the Human Rights Commission for justice, it will ultimately turn into a civil case requiring the intervention of state government departments like KRERA to provide relief. However, this can be done to put further pressure on state government departments to carry out the outstanding orders and implement the reliefs, they said.

"A person can file their complaints at multiple forums available, for example, RERA, national consumer forum, national tribunals or even the High Courts given that their request for reliefs are different for each case," D'souza.

Bengaluru real estate: Can homebuyers approach Human Rights Commission if the builder delays in handing over the flat?

https://www.hindustantimes.com/real-estate/bengaluru-real-estate-can-homebuyers-approach-human-rights-commission-if-the-builder-delays-in-handing-over-the-flat-101734533052835.html

BySouptik Datta Dec 19, 2024 09:37 AM IST

A Bengaluru buyer has approached the Human Rights Commission for relief after the builder delayed in handing over the flat despite several KRERA orders

Distressed over the delay in getting possession of his apartment and the compensation ordered by RERA, a homebuyer in Bengaluru has now approached the National Human Rights Commission.

The NHRC, in turn, wrote to the Karnataka State Human Rights Commission (KHRC), which has now written to the Karnataka RERA secretary and the deputy commissioner of the revenue department to take action and submit a report on the action taken to help the buyer, documents accessed by HT.com show.

“The delay is not just a breach of trust but also a violation of our fundamental right to a dignified life,” the buyer said in his complaint. Sudhakar Lakshmanaraja has been waiting for five years for his apartment in north Bengaluru to be delivered. The project was to be handed over by 2019.

"Despite multiple KRERA orders addressed to the deputy commissioner (revenue department) to recover the penalty from the builder, the builder has not paid us anything. Nothing has been resolved. As a last resort, I have approached the National Human Rights Commission and am waiting for justice," Lakshmanaraja was quoted as saying.

Submit report by January 9: KHRC

KHRC has written to the deputy commissioner of the revenue department that despite Lakshmanaraja's complaint to KRERA to recover the funds for the delayed apartment, the district collector's office is not following the orders of Karnataka RERA for the last two years.

“Take appropriate action and submit a report by January 9, 2024,” the notice sent on December 4 said.

This is what legal experts have to say

Legal experts say when a project is delayed in the state, the homebuyers can file a complaint at KRERA to recover their money. On its order, the state's revenue department will recover the amount, in the form of land arrears, from the respective developers.

In some cases, homebuyers have already invested over 80% of their savings to buy homes. "With multiple KRERA orders left to be fully executed and slow recovery at the revenue department, the homebuyers have started approaching the Commission as a last resort," Advocate Reynold D'souza said.

"After KRERA issues the recovery order, the deputy commissioner’s office (revenue dept) will notify the builder and recover the money. It is collected as revenue from land arrears. However, a slow recovery has left the homebuyers with no choice," Vittal BR, an advocate at the High Court of Karnataka, said.

According to a KRERA document dated August 2024, the Karnataka developers owe homebuyers more than ₹486 crore in refunds for delayed apartment delivery.

Can buyers file a complaint with the Human Rights Commission if their homes are delayed?

Legal experts said that after receiving a complaint, the Commission sends a notice to the respective government bodies to submit compliance reports.

"In this case, the Commission will send notice to the Karnataka RERA and the deputy commissioner (revenue department) to file their compliance reports within a certain period of time. This can be done to protect the homebuyers' right to life as they have invested significant funds and savings to purchase their dream homes," D'souza added.

Legal experts say that while homebuyers can approach the Human Rights Commission for justice, it will ultimately turn into a civil case requiring the intervention of state government departments like KRERA to provide relief. However, this can be done to put further pressure on state government departments to carry out the outstanding orders and implement the reliefs, they said.

"A person can file their complaints at multiple forums available, for example, RERA, national consumer forum, national tribunals or even the High Courts given that their request for reliefs are different for each case," D'souza.

NHRC discusses welfare of elderly with global experts

https://www.daijiworld.com/index.php/news/newsDisplay?newsID=1255003

Thu, Dec 19 2024 08:46:18 PM

New Delhi, Dec 19 (IANS): Suggestions on healthcare and nutritional needs of the elderly and their economic security, social inclusion, and quality of life from experts from the WHO, among others, dominated the agenda at a seminar organised by the National Human Rights Commission (NHRC) on Thursday.

Addressing the inaugural session, NHRC, Secretary General, Bharat Lal spoke about the evolving role of old age homes and the necessity for change and improvement in their functioning, a statement said.

Chairing the first thematic session on the health and nutrition needs of the elderly, Dr V. K. Paul, Member (Health), NITI Aayog, while sharing the concerns on the present and future challenges related to the well-being of the ageing population, commended the NHRC, India for its various initiatives in this regard.

Amit Yadav, Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment, chaired the second thematic session on economic security, social inclusion, and quality of life.

Several domain experts and eminent people, representatives of NGOs, academia, researchers, startups and medical fraternity attended the meet. After the speakers in each session, an open house was held to discuss the questions from the participants from various sectors including the WHO, United Nations Population Fund (UNFPA) and Tata Trusts.

The seminar ‘Ageing in India: Actionable Solutions - Drawing insights from Global, Regional, and National Best Practices’ was organised by the NHRC, in partnership with Sankala Foundation, along with the active participation of NITI Aayog and Ministry of Social Justice and Empowerment.

Earlier, NHRC, Secretary General, Bharat Lal emphasised that the Commission is working closely with civil society organisations, Special Rapporteurs and Monitors and human rights defenders to assess and advocate for elderly rights.

He said that it is time to work on an action-oriented model including the best practices for replication for the overall welfare of the elderly population in the country.

He urged for synergy among all organisations and said that an effort was on to develop a platform to provide elderly individuals with opportunities to engage and contribute to society, meaningfully.

TRIPURA STAR NEWS, Online, 20.12.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC, India & Sankala Foundation Organises A Day-Long Seminar On Ageing In India.

https://www.tripurastarnews.com/nhrc-india-sankala-foundation-organises-a-day-long-seminar-on-ageing-in-india/

December 19, 2024 4 min read

New Delhi, Delhi, 19th of December, 2024 : The National Human Rights Commission (NHRC), India in partnership with Sankala Foundation organised a day-long seminar on Ageing in India: Actionable Solutions- Drawing insights from Global, Regional, and National Best Practices along with the active participation of NITI Aayog and Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India, in New Delhi. The seminar concluded with several important suggestions regarding the healthcare and nutrition needs of the elderly and their economic security, social inclusion, and quality of life.

Addressing the inaugural session, NHRC, India Secretary General, Shri Bharat Lal spoke about the evolving role of old age homes and the necessity for change and improvement in their functioning. He emphasised that the Commission is working closely with civil society organisations, Special Rapporteurs and Monitors and human rights defenders to assess and advocate for elderly rights. He said that it is time to work on an action-oriented model including the best practices for replication for the overall welfare of the elderly population in the country. He urged for synergy among all organisations. He also said that an effort is on to develop a platform to provide elderly individuals with opportunities to engage and contribute to society, meaningfully.

Ms. Monali P. Dhakate, Joint Secretary, Ministry of Social Justice & Empowerment, elaborated on various government schemes and policies aimed at improving the quality of life of older persons and the ageing population in India. She also highlighted the provisions of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007, Atal Vayo Abhyuday Yojana (AVYAY), to name a few.

Shri Devendra Kumar Nim, Joint Secretary, NHRC, India highlighted the pressing issues elderly citizens face today and spoke about the ongoing initiatives by the National Human Rights Commission for elderly care.

Dr. Abha Jaiswal, Visiting Fellow, Sankala Foundation welcoming the participants said that India may be facing the concerns of a growing ageing population and therefore there is an urgent need for a comprehensive care mechanism for them. She underscored how addressing these needs could present significant opportunities for both economic growth and societal well-being.

Chairing the first thematic session on the health and nutrition needs of the elderly, Dr. V. K. Paul, Member (Health), NITI Aayog, while sharing the concerns on the present and future challenges related to the well-being of the ageing population, commended the NHRC, India for its various initiatives in this regard. Shri Amit Yadav, Secretary, Ministry of Social Justice & Empowerment, chaired the second thematic session on economic security, social inclusion, and quality of life. Several domain experts and eminent people, representatives of NGOs, academia, researchers, starts up and medical fraternity attended the meet. After the speakers in each session, an open house was held to discuss the questions from the participants from various sectors including the organisations like WHO, UNFPA and TATA Trusts.

Some of the suggestions were as follows:

i.) Develop a comprehensive health and nutrition package for the elderly;

ii.) Create specialized services to address the needs of elderly women;

iii.) Promote home- and family-based care initiatives;

iv.) Strengthen existing government schemes and models for elderly care;

v.) Explore partnerships with the private sector to make elderly care affordable and sustainable;

vi.) Encourage greater health insurance coverage for the elderly;

vii.) Learn from global best practices to firm up India’s approach to dealing with elderly care;

viii.) Develop a comprehensive and integrated family medicine vertical in the healthcare sector;

ix.) Ensure participation of the elderly population in the society with dignity, good health, and independence;

x.) Have a segregated database on the elderly population for targeted intervention;

xi.) Explore the scope for involvement of local bodies, including municipalities, as well as both public and private stakeholders in ensuring the rights of the elderly;

xii.) Make sure that the voices of the elderly are heard with due attention for their well-being.

The participants included Dr. Manashvi Kumar, Joint Secretary, Ministry of Health & Family Welfare; Shri C. K. Mishra, Former Secretary, Ministry of Health & Family Welfare; Dr. K. Madan Gopal, Advisor, National Health Systems Resource Centre; Dr.

Sanjay Wadhwa, Professor and Head, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, AIIMS, New Delhi; Prof. Rama Baru, Professor, JNU; Prof (Dr.) Manohar Agnani, Azim Premji University, Bhopal; Dr. Tanuja Nesari, Former Director, All India Institute of Ayurveda; Shri Manohar Lal Baharani, All India Senior Citizen Forum; Shri Puneet Kumar, Additional Chief Secretary, Social Justice Department, Kerala; Ms. Uma Devi, Joint Director, Social Justice Department, Tamil Nadu; Ms. Kajari Biswas, Senior Director, Ministry of External Affairs; Ms. Anupama Dutta, Helpage India; Ms. Pavithra Reddy, COO, Vayah Vikas; Shri Piyush Kumar, Founder, Khyaal App; Shri Asheesh Gupta, Co-founder, Samarth Elderly care, and Dr. G.P. Bhagat, Founder, SHEOWS, Shri K. Srinath Reddy, Honorary Distinguished Professor, Public Health Foundation of India, Ms. Amrita Kansal, Public Health Specialist, Healthy Ageing Vertical, WHO South East Asia Region and Dr. Manjari Chaturvedi, CEO, Healthy Aging India, among others.

This meet was the follow up to the national conference held on 18th October 2024 wherein various challenges faced by elderly were discussed. This discussion was focused on finding out solutions to these challenges. NHRC, India works with various stakeholders including various governments, both centre and states and their parastatal organisations, NGOs, human rights defenders and researchers.

NHRC and Sankala Foundation Address Elderly Care Needs in India: Insights and Actionable Solutions

https://www.devdiscourse.com/article/law-order/3200665-nhrc-and-sankala-foundation-address-elderly-care-needs-in-india-insights-and-actionable-solutions

Seminar Highlights Best Practices and Recommendations for Improving Elderly Welfare, Health, and Inclusion.

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 19-12-2024 22:44 IST | Created: 19-12-2024 22:44 IST

The National Human Rights Commission (NHRC) of India, in collaboration with Sankala Foundation, hosted a day-long seminar titled "Ageing in India: Actionable Solutions—Drawing Insights from Global, Regional, and National Best Practices". The seminar, held in New Delhi, brought together key stakeholders, including NITI Aayog, the Ministry of Social Justice and Empowerment, and various organizations, to address the pressing challenges faced by India's ageing population and propose actionable solutions.

The seminar focused on improving the healthcare, nutrition, economic security, and social inclusion of elderly citizens in India. Secretary General of NHRC, Shri Bharat Lal, emphasized the need for evolving and improving old-age home models, advocating for synergy among organizations and a platform to enable meaningful societal engagement for elderly individuals.

Keynote addresses by Ms. Monali P. Dhakate, Joint Secretary of the Ministry of Social Justice and Empowerment, and Shri Devendra Kumar Nim, Joint Secretary of NHRC, highlighted government schemes, such as the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007, and Atal Vayo Abhyuday Yojana (AVYAY), as well as NHRC's initiatives to improve elderly care.

Expert Insights and Discussions

Dr. Abha Jaiswal of Sankala Foundation opened the seminar by noting the urgency of addressing the needs of a growing ageing population. Dr. V. K. Paul, Member (Health) of NITI Aayog, chaired a thematic session on elderly health and nutrition, while Shri Amit Yadav, Secretary of the Ministry of Social Justice and Empowerment, led discussions on economic security and quality of life.

Prominent experts from organizations like WHO, UNFPA, TATA Trusts, AIIMS, JNU, and Azim Premji University contributed valuable insights during thematic sessions and open-house discussions.

Recommendations for Elderly Welfare

The seminar concluded with several actionable suggestions, including:

Health and Nutrition: Developing comprehensive packages for elderly health and nutrition and specialized services for elderly women.

Care Models: Promoting home- and family-based care while strengthening existing government schemes.

Partnerships: Exploring collaborations with private sector entities to ensure affordable and sustainable elderly care.

Insurance and Inclusivity: Expanding health insurance coverage and encouraging elderly participation in society with dignity and independence.

Data and Local Engagement: Creating a segregated database for targeted interventions and involving local bodies in elderly care initiatives.

Voices of the Elderly: Ensuring that the elderly's concerns and suggestions are prioritized.

Expanding NHRC's Vision for Elderly Rights

The event also served as a follow-up to the National Conference on Ageing held in October 2024, which had focused on identifying challenges faced by the elderly. The NHRC is committed to driving actionable solutions in partnership with central and state governments, NGOs, human rights defenders, and researchers.

Strengthening Future Collaborations

Participants emphasized learning from global best practices and fostering partnerships with public and private stakeholders to ensure the welfare of India's ageing population. Experts like Shri K. Srinath Reddy from the Public Health Foundation of India and Ms. Amrita Kansal from WHO underscored the importance of innovation and community-based solutions for healthy ageing.

This seminar marked a significant step in creating a roadmap for elderly care in India, reaffirming NHRC's dedication to promoting human rights and well-being for all age groups.

Ex-CJI Chandrachud's Appointment To New Role Faces Objection: Reports

https://www.pratidintime.com/top-stories/ex-cji-chandrachuds-appointment-to-new-role-faces-objection-reports-8531840

The decision to fill this position lies with a four-member selection committee comprising Prime Minister Modi, Home Minister Shah, Leader of Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi, and Leader of Opposition in the Rajya Sabha Mallikarjun Kharge.

Pratidin Time 19 Dec 2024 22:23 IST

The government's proposal to appoint recently retired Chief Justice of India D Y Chandrachud as the Chairman of the National Human Rights Commission (NHRC) has encountered strong resistance from key opposition leaders. Chandrachud retired last November, and Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah are reportedly keen to assign him the NHRC role.

The NHRC chairmanship has been vacant since July 1, following the retirement of former Chairman Arun Mishra. The decision to fill this position lies with a four-member selection committee comprising Prime Minister Modi, Home Minister Shah, Leader of Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi, and Leader of Opposition in the Rajya Sabha Mallikarjun Kharge.

During a recent meeting of the committee, both Gandhi and Kharge objected to the proposal of appointing Chandrachud to the NHRC. They are expected to submit a detailed report to the committee chair, outlining their reasons for opposing the appointment.

Sources suggest the opposition leaders raised concerns over Chandrachud's impartiality during his tenure as Chief Justice of India. Allegations of a close relationship between Chandrachud and the Prime Minister have also added to the controversy. A widely circulated photograph showing Chandrachud attending a Ganesh Puja at his residence, which was also attended by Prime Minister Modi, has fueled further skepticism among opposition leaders and civil society groups.

Notably, the NHRC chairmanship has historically been held by former Chief Justices of the Supreme Court, including KG Balakrishnan and HL Dattu. Despite this precedent, opposition leaders argue that appointing Chandrachud could undermine public confidence in the commission's impartiality.

The government remains committed to filling the vacancy at the NHRC, but the objections from the opposition leaders indicate a challenging path ahead for consensus.